

Q.: द्विव्य संघीय न्यायालय के संघर्ष, इतिहास तथा कार्य का वर्णन करें
 Ans.: संघीयता के अंतर्गत एक स्वतंत्र व विपक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। लेकिन द्विव्य संविधान के निर्माता इस बात में विश्वास रखते हैं कि द्विव्य संघीयता की सर्वोच्च सत्ता सौंपी जाए न्यायपालिका और न्यायपालिका को उसके निर्माण में उत्ती जाय। इस दृष्टि से द्विव्य संघीय न्यायालय अमेरिकी न्यायालय के समान स्वतंत्र नहीं है। द्विव्य कार्यपालिका ने वर्तमान में अपने प्रभाव को बढ़ाया है, लेकिन द्विव्य न्यायपालिका अभी भी द्विव्य संघीय व्यवस्था में तीसरे स्थान पर है।

निर्वाचन और कार्यकाल : द्विव्य संघीय व्यवस्थापिका अपने अधिवेशन में 6 वर्ष के लिए न्यायधीमों का निर्वाचन करती है। इसके 26 जज तथा 12 उनके सहयोगी न्यायधीम जज हैं। व्यवस्थापिका इन न्यायधीमों में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। इनके दो-दो वर्ष के लिए चुना जाता है तथा इनके दुबारे निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं। द्विव्य संघीय व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है कि न्यायधीम पुनः निर्वाचित हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते। इसके चलते वहाँ न्यायधीम लगातार स्थानी जैसा ही जजा है।

द्विव्य संविधान में न्यायधीमों की शक्ति का वर्णन के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वह प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने की शक्ति रखता है तथा संघीय परिषद या संघीय संसद का अध्यक्ष नहीं है, न ही वह सहाय्य अधिकारी के पद पर है। एक यह बात भी ध्यान में रखनी है कि न्यायधीमों का निर्वाचन में तीनों राष्ट्रभाषा जर्मन, फ्रेंच व इटालियन भाषी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यह ही है कि न्यायधीमों के निर्वाचन के लिए द्विव्य संविधान उसी व्यवस्था को तैयार करे है कि इसे विधि का ज्ञान होना चाहिए लेकिन व्यवहार में यह परम्परा बन गई है कि उन्ही न्यायधीमों को निर्वाचित दिया जाता है जो आपराधिद मामलों में विशेषज्ञता व अभ्युक्त

7

उत्पन्न है। इसका कार्यात्मक बाड प्रान्त के लार्डेन तर्ज
में है। एड इन्फ्रमर का निगा है कि विविध न्यायिको हाइकोर्ट
इस सुपरिचित प्रणाली पर आधारित है कि न्याय सेवाधिकार
के सुपरिचित प्रणाली पर आधारित है कि न्याय सेवाधिकार
है वाकि तन्मो को विनिकुर्ण्ड समझने तथा उनका
मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है।

न्यायधीनता में 53000 फ़ैड प्रतिवर्ष
केतन मिलता है। अक्षय का इसमें करिब 13600 तथा
तुपाय को 2400 फ़ैड नार्थिक न्याय मिलता है। केंद्रिय
न्यायधीनता को केतन नहीं मिलता है। उन्हे सिर्फ़ इन्ही दिनों
का भता मिलता है जिन दिनों में वे न्यायालयों में कार्यरत
हैं। न्यायधीनता को 40 से 60 प्रतिशत तक उन्के केतन
का संभन करने की व्यवस्था है। उनकी संविक्रिति की आयु
60 वर्ष है।

कार्य की दृष्टि से फ़ेडरल ट्रिब्युनल अर्थात्
संघीय न्यायालय को चार भागों में बांटा गया है -
प्रथम, सांविधानिक कानून से सम्बन्धित विवादों के
निर्णय के लिए, द्वितीय, चक्र और दिवाणियों से सम्बन्धित
तथा अप्र को दीवानी मामलों पर निगर करती है। इसे
ट्रिब्युनल को वर्षों के लिए नियुक्त करा है। फ़ौजदारी
मामलों के लिए न्यायालय चार भागों में बांटे हैं -
① फ़ौजदारी (Criminal Chamber), ② संघीय दण्ड
विभाग (Federal penal Court) ③ चेंबर ऑफ़
कम्प्लेंट्स (Chamber of Complaints) तथा
सांविधानिक विभाग (Court of Cessation)
समस्त समस्त पर फ़ौजदारी विभाग भ्रमणशील
न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है।

सौत्रापिकार - संघीय न्यायालय का सेवाधिकार
दो प्रकार का है 1. प्रारंभिक 2. अपीलिय।
1. प्रारंभिक सेवाधिकार को चार भागों में बांटा जा
सकता है ① दीवानी क्षेत्र -